(e) whether the competent authorities issuing Exim Scrips are not able to cross-check the authenticity of the bank issuing the documents; and

(f) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir.

(b) Exim scrips scheme has since been discontinued.

(c) to (f) Some cases have been detected where Exim scrips were issued based on documents subsequently found to be forged. The matter has been handed over to the police for appropriate action.

Indication of details of STD Call availed in bills

2908. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the details of STD calls availed by a consumer are given in the telephone bills only in some areas in Madras city; and

(b) if so, what steps are being taken to supply these details in the monthly telephone bills of all telephone subscribers in Madras city?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes Sir.

(b) Details of STD calls availed by subscriber are given only to the subscribers at present served by electronic exchanges. Out of 35 exchanges in Madras Telephone District only 21 (49.5% of the Total Capacity) are of electronic type for the remaining 14 exchanges (50.5% of the total capacity) it is not technically possible to provide details of STD calls to the subscribers at present. This will be possible after the exchanges are replaced by electronic exchanges.

मध्य प्रदेश के कोयला बाहुल्य क्षेत्रों में एस०टी०डी० सुविधा

2909. **श्री अजीत जोगी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के कोयला बाहुल्य क्षेत्रों के महत्वपूर्ण व्यावसायिक नगरों को एस०टी०डी० सुविधा शीघ्र देने की मांग कुछ जनप्रतिनिधियों तथा अन्य संस्थाओं ने की है;

(ख) यदि हां, तो इन नगरों को एस०टी०डी० सुविधा कब तक मिल जायेगी; और

(ग) सरगुजा जिले के सूरजपुर और विश्रामपुर तथा चिरसिरी जैसे नगरों की एस०टी०डी० सुविधाओं से कब तक जोड़ दिया जायेगा?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू): (क) जी, हां।

(ख) शहडोल, छिंदवाड़ा और सिंगरौली में एस०टी०डी० सुविधा पहले ही प्रदान कर दी गई है। सिधी में मार्च, 92 के अंत तक और परसिया में वर्ष 1993-94 के दौरान यह सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है।

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान।

मध्य प्रदेश के ब्लॉकों और गांवों में टेलीफोन सुविधाएं

2910. **श्री अजीत जोगी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के ब्लॉकों और पंचायत मुख्यालयों की संख्या कितनी-कितनी है जहां अभी तक टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश ब्लॉक और पंचायत मुख्यालय पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं;

(ग) सरकार की उन्हें सीधी टेलीफोन सुविधा से जोड़ने की क्या योजना है; और

(घ) इन पंचायत मुख्यालयों को कब तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू): (क) सभी ब्लॉक मुख्यालयों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है और 16,652 पंचायतों को टेलीफोन सुविधा अभी प्रदान की जानी है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) सरकार ने 31 मार्च, 1995 तक सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को टेलीफोन सुविधा से